

## ‘संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना’ की बहाली

### प्रलिस के लयः

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA), अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ।

### मेन्स के लयः

JCPOA की समयरेखा एवं पृष्ठभूमि, JCPOA की बहाली के भारत पर प्रभाव ।

## चर्चा में क्यों?

ईरान के साथ वर्ष 2015 के अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते को पूरव रूप में लाने पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अपर्यक्ष वार्ता के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु सहयोग परियोजनाओं को अनुमति देने के लिये **ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट को बहाल** कर दिया है ।

- सुरक्षा एवं अपरसार को बढ़ावा देने के नाम पर यह छूट अन्य देशों और कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कयि बनिईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देती है ।
- पूरव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जनिहोंने इस परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया था, के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019 और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस छूट को रद्द कर दिया गया था । इस समझौते को औपचारिक रूप से **संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना** (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) के नाम से जाना जाता है ।

## क्या है JCPOA की सामयकता एवं पृष्ठभूमि?

- JCPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ) के बीच वर्ष 2013-2015 के दौरान चली लंबी बातचीत का परिणाम था ।
- यह ओमान की मध्यस्थता के साथ अमेरिका (राष्ट्रपति बराक ओबामा के तहत) और ईरान के बीच आयोजित बैक चैनल वार्ताओं के कारण संभव हो सका, ये वार्ताएँ वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उत्पन्न स्थिति में पुनः विश्वास बहाली के प्रयासों का हिस्सा थीं ।
  - **इस्लामिक क्रांति**, जसि ईरानी क्रांति भी कहा जाता है, वर्ष 1978-79 के दौरान ईरान में एक लोकप्रिय विद्रोह था, जसिके परिणामस्वरूप 11 फरवरी, 1979 को राजशाही का पतन हुआ और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई ।
- JCPOA ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने के बदले में एक अंतरवैधी निरीक्षण प्रणाली की नगिरानी में उसे अपने परमाणु संवर्द्धन कार्यक्रम को सीमित करने के लिये बाध्य कयिा ।
  - हालाँकि एक आक्रामक रिपब्लिकन सीनेट के कारण राष्ट्रपति ओबामा इस परमाणु समझौते पर सीनेट से मंजूरी प्रदान कराने में असमर्थ रहे थे, परंतु ईरान पर लगे प्रतिबंधों में छूट के लिये इसे आवधिक कार्यकारी आदेशों के आधार पर लागू कयिा गया ।
- डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वे इस समझौते से पीछे हट गए, उन्होंने इसे एक "बहुत ही खराब, एकतरफा सौदा बताया, जसि कभी नहीं लागू कयिा जाना चाहयिा था ।"
- अमेरिका के इस समझौते से अलग होने के नरिणय की JCPOA में शामिल अन्य सदस्यों (यूरोपीय सहयोगियों सहति) ने आलोचना की क्योंकि उस समय तक ईरान इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रहा था और **अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी** (IAEA) द्वारा इसे प्रमाणित भी कयिा गया था ।
- ईरान पर अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंधों की सख्ती के कारण दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया, अमेरिकी प्रतिबंधों के वसितार के साथ वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जुड़े लगभग सभी ईरानी **बैंक, धातु, ऊर्जा और शपिगि से संबंधित उद्योग, रक्षा, खुफिया तथा परमाणु प्रतिष्ठानों** से संबंधित लोग आदि सभी इसके दायरे में आ गए थे ।
- अमेरिका के इस समझौते से पीछे हटने पर पहले वर्ष में ईरान की तरफ से कोई प्रतिकरिया नहीं देखने को मली क्योंकि इस दौरा **E-3 देशों (फ्रांस, जर्मनी, यू.के.)** और यूरोपीय संघ ने अमेरिकी फौसले के प्रभावों को कम करने हेतु समाधान खोजने का वादा कयिा था ।
  - E-3 देशों ने **‘इंस्टेक्स’** (Instrument in Support of Trade Exchanges- INSTEX) के माध्यम से कुछ राहत प्रदान करने का वादा कयिा, ध्यातव्य है कि इंस्टेक्स की स्थापना वर्ष 2019 में ईरान के साथ सीमित व्यापार की सुवधि के लिये की गई थी ।
- हालाँकि भई 2019 तक **ईरान का यह रणनीतिक धैर्य** समाप्त हो गया क्योंकि वह E-3 देशों से अपेक्षित आर्थिक राहत पाने में वफिल रहा ।

- ऐसे में जब ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव तीव्रता से पड़ने लगा तो ईरान ने 'अधिकतम प्रतिबंध' की रणनीति अपनानी शुरू कर दी।

## Changes agreed under Iran deal to limit nuclear programme



//

## JCPOA की बहाली से कैसे प्रभावित होगा भारत?

JCPOA की बहाली से ईरान पर लगाए गए कई प्रतिबंधों में कटौती हो सकती है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ भारत को मिल सकता है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के आधार पर समझा जा सकता है:

- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा:** ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने से [चाबहार](#), बंदर अब्बास बंदरगाह और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित अन्य योजनाओं में भारत के हितों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।
  - यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थिति को बेअसर करने में भारत की मदद करेगा।
  - चाबहार के अलावा ईरान से होकर गुजरने वाले 'अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे' (INSTC) से भारत के हितों को भी बढ़ावा मिल सकता है। गौरतलब है कि INSTC के माध्यम से पाँच मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** अमेरिका की आपत्तियों और [CAATSA \(Countering America's Adversaries Through Sanctions Act\)](#) के दबाव के कारण भारत को ईरान से तेल के आयात को शून्य करना है।
  - अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की बहाली से भारत को ईरान से सस्ते तेल की खरीद करने तथा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**